



दवियांगजनों के लयि सम्मान और समानता का भवषिय

12/09/2025 “Humour targeted at disabled reveal a troubling mindset”

प्रलमिस के लयि: अनुच्छेद 15 और 21, दवियांगजन अधकार अधनियम, 2016, दवियांगजन अधकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, पीएम-दकष योजना, युनीक डसिबिलिटी आईडी सकीम, दविय कला मेला, युनेस्को, दवियांगजनों की शकषिा के लयि वशिष मान्यता प्रापत संसथान

मेन्स के लयि: दवियांगजनों के समावेशन और सशकतीकरण में भारत द्वारा की गई प्रमुख प्रगत, भारत में दवियांगजनों के समावेशन और सशकतीकरण में प्रमुख बाधाएँ

हाल की सोशल मीडिया और मनोरंजन उदयोग की घटनाएँ यह दर्शाती हैं क दवियांगजन अब भी सूक्ष्म प्रकार के बहषिकरण का सामना करते हैं—कभी सामाजिक परप्रेक्ष्य में उपेक्षति होकर तो कभी हास्य का वषिय बनाकर प्रस्तुत कयि जाने के माध्यम से। (2024) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्मरण कराया क अभवियकती की स्वतंत्रता नसिंदेह महत्त्वपूर्ण है, परंतु यह संवधान के अनुच्छेद 15 और 21 में नहिति गरमा एवं समानता के मूल्यों के अनुरूप ही प्रयोग की जानी चाहयि। दवियांगजनों के अधकार अधनियम, 2016 भी इन संरक्षणों को वधिकि आधार प्रदान करता है तथा सम्मान और समावेशन के सिद्धांतों की पुष्टि करता है। वास्तवकि सशकतीकरण तभी संभव है जब इन बाधाओं को दूर कयि जाए, दवियांगजनों को सही और सम्मानजनक प्रतनिधित्व मलि, नीतयिा समावेशी हों तथा समाज की सोच में यह बदलाव आए क दवियांगता कोई कमी नहीं, बलक भानवीय वविधिता का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है।

दवियांगजनों के समावेशन और सशकतीकरण में भारत ने कया प्रमुख प्रगत की है?

- प्रगतशील कानूनी ढाँचा और अधकार-आधारति दृष्टिकोण: दवियांगजन अधकार (RPWD) अधनियम, 2016, पहले के दवियांगजन अधनियम, 1995 में वसितार के साथ एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।
- इस नए कानून ने मान्यता प्रापत दवियांगजनों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दया है, जो क दवियांगजनों के अधकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) के अनुरूप है।
- इसमें सरकारी नौकरयिों में 4% तथा उच्च शकषिा संसथानों में 5% आरक्षण का प्रावधान कयि गया है, जससे दवियांगजनों के समानता, सम्मान एवं गैर-भेदभाव के अधकार को मज़बूती मलिंगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन अधकारों को सक्रयिता से बरकरार रखा है, जसा क हाल ही में 2025 के फैसले में देखा गया है, जसमें न्यायकि सेवाओं से दृष्टिबाधति उम्मीदवारों को बाहर करने के खलिाफ फैसला सुनाया गया था।
- समावेशी अवसंरचना और गतशीलता: वर्ष 2015 में शुरू कयि गया सुगम्य भारत अभयान दवियांगजनों के लयि बाधा-मुक्त वातावरण बनाने की एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है।
- यह तीन प्रमुख क्षेत्रों नरिमति पर्यावरण, परविहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), में सुगम्यता को लक्षति करता है।
- इस अभयान के कारण सरकारी भवनों और सार्वजनकि परविहन प्रणालयिों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धा हुई है।
- उदाहरण के लयि, वर्ष 2022 तक, 2016-2017 में पहुँच ऑडिट के दौरान पहचाने गए लगभग आधे राज्य और केंद्रशासति प्रदेशों के सरकारी भवनों को सुगम्य बना दया गया है।
 - आर्थकि सशकतीकरण और कौशल वकिस: सरकार ने दवियांगजनों की आर्थकि स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लयि कई लक्षति योजनाएँ शुरू की हैं।

- प्रधानमंत्री-दक्ष योजना और दवियांगजनों के कौशल विकास के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सहायता प्रदान करती है।
- सहायक उपकरणों की खरीद/फटिंग के लिये दवियांगजनों को सहायता (ADIP) योजना सहायक उपकरणों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
 - राष्ट्रीय दवियांगजन वित्त एवं विकास नगिम दवियांगजन उद्यमियों को रणियती दरों पर ऋण प्रदान करता है।
- तकनीकी और डजिटल समावेशन: कमियों को कम करने में तकनीक की शक्ति को पहचानते हुए, भारत व्यापक डजिटल समावेशन पर जोर दे रहा है। सरकार की ई-गवर्नेंस पहल अब वेब सुलभता को प्राथमिकता दे रही है, कई सार्वजनिक वेबसाइटें वेब सामग्री सुलभता दशा-नरिदेशों (WCAG) का पालन कर रही हैं।
 - अद्वितीय दवियांगता पहचान-पत्र (यूडीआईडी) परियोजना एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जो दवियांगजनों का एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस तैयार करेगी तथा एक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएगी, जो दवियांगता के प्रमाण के रूप में कार्य करेगा।
- शैक्षिक समावेशन और छात्रवृत्तियोजनाएँ: नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 समावेशी शिक्षा पर जोर देती है, जो दवियांग छात्रों के लिये अधिकार-आधारित ढाँचे को बढ़ावा देती है।
- सरकार ने प्री-मैट्रिकुलेशन से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएशन तक दवियांग छात्रों को सहायता देने के लिये कई छात्रवृत्तियोजनाएँ शुरू की हैं।
- दवियांगजनों के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्तियोजना ने हजारों छात्रों को सहायता प्रदान की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दवियांगजनों में ऐतहासिक रूप से कम रही साक्षरता दर और शिक्षा में नामांकन की दर को बढ़ाना है।
- जागरूकता और समावेशी आख्यानो को बढ़ावा देना: कानूनी सुधारों के अलावा, सामाजिक दृष्टिकोण को दान-आधारित से अधिकार-आधारित परिप्रेक्ष्य में बदलने के लिये सचेत प्रयास किया जा रहा है।
 - वार्षिक 'दविय कला मेला' जैसी पहल दवियांगजनों की कलात्मक और उद्यमशील प्रतभा को प्रदर्शित करती है, रूढ़िवादिता को चुनौती देती है तथा उनमें गौरव एवं सम्मान की भावना को बढ़ावा देती है।
 - सरकार द्वारा 'दवियांगजन' शब्द का प्रयोग, दवियांगता को एक सीमा की बजाय एक अद्वितीय क्षमता के रूप में पुनः परिभाषित करने के व्यापक बदलाव का हिस्सा है।
 - पैरालंपिक जैसे वैश्विक मंच पर भारतीय पैरा-एथलीटों की बढ़ती सफलता इस सकारात्मक कहानी को और बढ़ाती है।
- वकिंद्रीकृत एवं समन्वयित शासन: वर्ष 2012 में दवियांगजन सशक्तीकरण वभाग (DEPwD) की स्थापना ने दवियांगजनों से संबंधित मुद्दों पर समर्पित और संगठित संस्थागत ध्यान सुनिश्चित किया।
 - यह वभाग भारतीय पुनर्वास परषिद और वभिन्नि राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मलिकर नीति कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करने तथा देश भर में पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने का कार्य करता है।
 - कई जिलों में जिला दवियांगता पुनर्वास केंद्रों (DDRCs) की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में दवियांगजनों को आवश्यक सेवाएँ उनके नकिट ही उपलब्ध होने लगीं। इसके परिणामस्वरूप पेशेवर मार्गदर्शन, पुनर्वास सेवाओं और सहायक उपकरणों तक उनकी पहुँच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

भारत में दवियांगजनों के समावेशन और सशक्तीकरण में कौन-सी महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं?

- दुरगम अवसंरचना और बढ़ता डजिटल वभागजन: दुरगम अवसंरचना और बढ़ते डजिटल वभागजन के कारण, सुगम्य भारत अभियान जैसे नीतगित प्रयासों के बावजूद शहरी जड़ाइन एवं परिवहन प्रणालियाँ अब भी बहषिकारवादी बनी हुई हैं। यह सथति एक गहराई से जमे हुए वास्तुशिल्प रंगभेद' की ओर संकेत करती है, जहाँ दवियांगजन अब भी मूलभूत सेवाओं और अवसरों से वंचित रह जाते हैं।
- अधिकांश सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कार्यस्थलों में रैम्प, स्पर्शनीय पथ या सुलभ शौचालयों का अभाव है, जिससे दैनिक आवागमन एक संघर्ष बन जाता है।
- डजिटल मोर्चे पर, सुगम्यता मानकों का अनुपालन न करने के कारण दवियांगजन ई-गवर्नेंस, बैंकिंग और टेलीहेल्थ प्लेटफॉर्मों से वंचित रह जाते हैं।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत दवियांगजनों के लिये डजिटल पहुँच को मौलिक अधिकार माना है, लेकिन इसका कार्यान्वयन असंगत बना हुआ है।
 - फरवरी 2025 में, दवियांगजनों के लिये मुख्य आयुक्त (CCPD) न्यायालय ने डजिटल सुलभता मानकों का पालन न करने के लिये 155 नजिी और सरकारी संगठनों को दंडित किया।
- यह दोहरा बहषिकार, भौतिक और डजिटल, स्वतंत्र जीवन को सीमति करता है तथा संरचनात्मक असमानताओं को बढ़ाता है।
- समावेशी शिक्षा में कमियाँ: शिक्षा प्रणाली वास्तव में समावेशी होने की बजाय बड़े पैमाने पर एकीकरणवादी बनी हुई है तथा प्रायः दवियांगजनों को उपेक्षित माना जाता है।
- विशेष शिक्षकों, सहायक प्रौद्योगिकियों और समावेशी शिक्षण पद्धतियों की कमी प्रभावी शिक्षण परिणामों को सीमति करती है।
- दुरगम स्कूल अवसंरचना एवं कठोर मूल्यांकन पद्धतियें दवियांगजन बच्चों को और अधिक हाशिये पर धकेलती हैं।
- इसका परिणाम नमिन नामांकन, उच्च ड्रॉपआउट दर और बहषिकरण का अंतर-पीढ़ी चक्र है।
 - भारत में 5 वर्ष की आयु के तीन-चौथाई दवियांग बच्चे और 5-19 वर्ष की आयु के एक-चौथाई दवियांग बच्चे किसी भी शैक्षिक संस्थान में नहीं गए। (यूनेस्को रिपोर्ट 2019)
- यह शैक्षिक अंतर रोजगार क्षमता में कमी लाता है तथा आर्थिक असुरक्षा को बढ़ाता है।
- रोजगार अपवर्जन और कार्यस्थल भेदभाव: दवियांगजन अधिनियम के तहत वैधानिक आरक्षण के बावजूद, कार्यान्वयन संबंधी बाधाएँ और मनोवृत्तगित पूर्वाग्रह दवियांगजनों को सारथक रोजगार से वंचित रखते हैं।
- नजिी क्षेत्र में नयिकृतियों प्रतीकात्मक बनी हुई हैं तथा कार्यस्थल पर उचित व्यवस्था या अनुकूल भूमिकाओं पर सीमति ध्यान दिया जा रहा है।
- कौशल विकास पारसिथितिकी तंत्र, सुलभ नौकरी पोर्टल एवं नयिकता संवेदनशीलता का अभाव इस चुनौती को और बढ़ा देता है।
 - सरकारी आँकड़े बताते हैं कि 2.6 करोड़ दवियांगजनों में से केवल 36% ही रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से, पुरुषों के रोजगार प्राप्त करने की संभावना महिलाओं की तुलना में ज्यादा है, जहाँ 47% पुरुषों को नौकरी मिलती है, जबकि महिलाओं के लिये यह आँकड़ा 23% है।

- परिणामस्वरूप, दवियांगजन अनोपचारिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रतनिधित्व करते हैं, उन्हें ऊपर की ओर बढ़ने की सुविधा तथा आर्थिक सम्मान से वंचित रखा जाता है।
- स्वास्थ्य देखभाल की अनुपलब्धता और उपेक्षा:** दवियांगजनों के लिये स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रणालीगत उपेक्षा और विशेष देखभाल के अभाव से ग्रस्त हैं।
 - एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत में 80% से ज्यादा दवियांगजन स्वास्थ्य बीमा के बिना रह गए हैं, जबकि 53.2% दवियांगजन के आवेदन बार-बार अस्वीकार किये जाने के कारण वे बीमा कवरेज प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
 - इसके अलावा, अस्पतालों में सांकेतिक भाषा या पुनर्वास चिकित्सा जैसी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है।
 - नविरक और पुनर्वास देखभाल अभी भी अवकिसति है, जिसके कारण द्वितीयक स्थितियों अनुपचारित रहती हैं।
 - महामारी ने इन खामियों को उजागर किया है, जहाँ दवियांगजनों को डिजिटल टेलीहेल्थ, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और टीकाकरण अभियानों से वंचित रखा गया। चिकित्सा के क्षेत्र में यह हाशिये पर धकेला जाना जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व, दोनों को कमजोर करता है।
- नीति-अंतराल और कमजोर शासन:** भारत में RPWD अधिनियम 2016 जैसे प्रगतशील कानून होने के बावजूद, उनका प्रभावी क्रियान्वयन बाधित रहता है। कमजोर शासन-व्यवस्था, अपर्याप्त नगिरानी एवं जवाबदेही की कमी इस प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देती है।
 - कई राज्यों में सलाहकार बोर्ड, सुगम्यता ऑडिट और शकियत नविरण तंत्र या तो अनुपस्थित हैं या नषिक्रयि हैं।
- दवियांगजन के मुद्दों को प्रायः कल्याण विभागों के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे शिक्षा, शर्म और शहरी विकास के साथ अंतर-क्षेत्रीय समन्वय कम हो जाता है।
 - वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि कई राज्य आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, जैसे राज्य आयुक्तों की नियुक्ति, को लागू करने में वफिल रहे हैं।
 - परिणामस्वरूप, कानूनी अधिकारों के ज़मीनी प्रभाव के बिना 'कागज़ी अधिकार' बने रहने का खतरा है, जिससे संस्थाओं में विश्वास कम हो रहा है।
- आँकड़ों की कमी और सूचना के अस्पष्ट क्षेत्र:** दवियांगजन से संबंधित सटीक आँकड़े दुर्लभ, पुराने और विभिन्न स्रोतों में बखिरे हुए हैं। सीमति परिभाषाओं वाली 2011 की जनगणना पर निर्भरता, दवियांग जनसंख्या का गंभीर रूप से कम आकलन करती है।
 - प्रकार, लिंग और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर वास्तविक समय (Real-time) में अलग-अलग आँकड़ों की अनुपस्थिति लक्षित हस्तक्षेपों में बाधा डालती है।
 - भारत के 50% से भी कम दवियांगजनों के पास यूनिके डिसिबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड है, जिसके कारण उन्हें सरकारी लाभों तक पहुँचने में कठिनाई होती है। इसका कारण देरी और डिजिटल साक्षरता की कमी है।
 - मज़बूत साक्ष्य के अभाव में नीति-निरीमाता बजट नयिजन, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रभाव की नगिरानी में गंभीर अंध बट्टियों का सामना करते हैं।
 - डेटा सत्र पर अदृश्यता, विकास की चर्चा में भी अदृश्यता का कारण बन जाती है।
- गहरी जड़ें जमाए सामाजिक और रोज़मर्रा का भेदभाव:** समाज में दवियांगजनों को अब भी दान और आश्रितता की दृष्टि से देखा जाता है, जिससे उनके अधिकारों एवं स्वायत्तता की उपेक्षा होती है।
 - यह भेदभाव प्रायः परिवार सत्र से ही शुरू हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा में नविश की कमी और आंतरिक बहिष्करण सामने आते हैं।
 - सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव के कारण सामाजिक भागीदारी सीमति हो जाती है तथा सांस्कृतिक संवाद में अदृश्यता आ जाती है।
 - यह 'अन्यीकरण' बहिष्कार के चक्र को जारी रखता है, जहाँ दवियांगजनों को समाज के योगदानकर्त्ता के रूप में नहीं, बल्कि बोझ के रूप में देखा जाता है। इसे तोड़ने के लिये दृष्टिकोण में बदलाव और मूल्य पुनर्संरचना की आवश्यकता है।

दवियांगजनों के लिये अधिक समावेशी और सशक्त भवषिय के नरिमाण हेतु भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- अवसंरचना और प्रौद्योगिकी में सार्वभौमिक डिज़ाइन: सभी नए सार्वजनिक अवसंरचना, आवास और गतशील प्रणालियों में सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धांतों को लागू करने के लिये केवल सांकेतिक पहुँच से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
- शहरी नयिजन संहिताओं, स्मार्ट सिटी परयिोजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों में सुगम्यता मानकों को रेट्रोफिटिंग की बजाय ब्लूप्रिंट स्ट्रेज से ही एकीकृत किया जाना चाहिये।
- नवाचार केंद्रों के माध्यम से सहायक प्रौद्योगिकियों, आवाज़-सक्षम सेवाओं और समावेशी फनिटेक उपकरणों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- इस तरह का एकीकरण सुलभता को कल्याणकारी पूरक की बजाय मुख्यधारा की विकास प्राथमिकता के रूप में सामान्य बनाता है।
 - वाराणसी की 'सुगम्य काशी' परकिल्पना सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- समावेशी शिक्षा तंत्र: कक्षाओं में केवल एकीकरण पर नहीं, बल्कि वास्तविक समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। इसके लिये सुलभ पाठ्यक्रम, विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध शिक्षण-सामग्री और दवियांगता-संवेदनशील शिक्षाशास्त्र में प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है।
- प्रत्येक ज़िले में संसाधन केंद्र स्थापित करना, ताकि मुख्यधारा के स्कूलों को सहायक उपकरण और विशेष शिक्षक उपलब्ध कराए जा सकें।
- डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म में समावेशी प्रथाओं को शामिल करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हाइब्रिड लर्निंग मॉडल में कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। इस प्रकार की पहलें प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों में गरमा, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना को पोषित करती हैं।
 - दवियांगजनों की शिक्षा के लिये विशेष मान्यता प्राप्त संस्थान सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- समतामूलक रोज़गार और कार्यस्थल परिवर्तन: सार्वजनिक और नजी, दोनों क्षेत्र के संस्थानों के लिये समावेशी भरती ऑडिट को अनविर्य बनाया जाना चाहिये, प्रोत्साहन एवं कर लाभों को विधिता परिणामों से जोड़ना चाहिये।
- हरति ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और दवियांगजनों की क्षमताओं के अनुरूप रचनात्मक उद्योगों जैसे उभरते क्षेत्रों में समरपति कौशल

पाइपलाइनों का निर्माण कराया जाना चाहिये।

- **उच्चति समायोजन और अनुकूल कार्य मॉडल** लागू किया जाना चाहिये, विशेषकर दूरस्थ एवं गगि-आधारित कार्यों में। ऐसे प्रणालीगत सुधार रोजगार क्षमता को दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तीकरण में बदल देते हैं।
- **स्वास्थ्य एवं पुनर्वास नरितरता:** स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की नरितरता सुनिश्चित करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, टेलीमेडिसिन सेवाओं और बीमा योजनाओं में दवियांगता-समावेशी प्रोटोकॉल को शामिल करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के वतिरण को पुनः डिज़ाइन किया जाना चाहिये।
- फज़ियोथेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य, कृत्रिम अंग (Prosthetics) और समुदाय-आधारित देखभाल को समाहित करने वाला एक मज़बूत **राष्ट्रीय पुनर्वास नेटवर्क** विकसित किया जाना चाहिये, जिससे दवियांगजनों को व्यापक एवं सतत सहयोग मिल सके।
- सेवा वतिरण में गरमि और सम्मान सुनिश्चित करने के लिये चकितिसा एवं स्वास्थ्यकरमियों को दवियांगता-संवेदनशील प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- **नविरक और पुनर्वास देखभाल** में नविश न केवल जीवन रक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता एवं स्वायत्तता भी सुनिश्चित करता है।
- **सामाजिक दृष्टिकोण परविरतन:** सामाजिक दृष्टिकोण में परविरतन लाने के लिये आवश्यक है कि दवियांगता से संबंधित चर्चा को जनसंचार माध्यमों, लोकप्रिय संस्कृत और नागरिक अभियानों की मुख्यधारा में स्थान दिया जाए। साथ ही, दान और आशरतिता पर आधारित कहानियों के स्थान पर सशक्तीकरण, अधिकारों एवं उपलब्धियों पर केंद्रित कहानियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **स्कूल नागरिक शास्त्र और कॉर्पोरेट संवेदीकरण कार्यक्रमों में दवियांगता अधिकार शक्ति** को एकीकृत किया जाना चाहिये। स्थानीय सामुदायिक पहलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जो दवियांगजनों को नेतृत्वकर्त्ता, उद्यमी और नवप्रवर्त्तक के रूप में प्रदर्शित करती हों।
- यह दृष्टिकोणगत बदलाव उन्हें **‘देखभाल के प्राप्तकर्त्ता’ से समाज की विकास गाथा में समान हतिधारकों** में बदल देता है।
- **शासन और नीतगत जवाबदेही:** वभिन्न क्षेत्रों में समन्वय के लिये **दवियांगता समावेशन** पर एक एकीकृत मशिन की स्थापना करके खंडित कल्याणकारी योजनाओं से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
- **समयबद्ध कार्यान्वयन ऑडिट**, वास्तविक काल पर शकियत नविरण तथा दवियांगजन समूहों द्वारा स्वयं संचालित सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **बजट उपयोग और परिणामों में पारदर्शिता के लिये डिजिटल डैशबोर्ड एवं ओपन डेटा पोर्टल** का प्रयोग किया जाना चाहिये। मज़बूत शासन वधियी मंशा को ज़मीनी स्तर पर ठोस बदलाव में परविरतित कर देता है।
- **नीतगत सटीकता के लिये डेटा और नवाचार:** नीतगत सटीकता सुनिश्चित करने के लिये वसितृत, **पृथक और नरितर अद्यतन डेटा पर आधारित एक गतशील राष्ट्रीय दवियांगता रजिस्ट्री** स्थापित की जानी चाहिये। साथ ही, पहुँच और सेवा वतिरण में कमियों की पहचान करने हेतु **AI-ड्रिविन एनालिसिस** तथा **GIS मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग** किया जाना आवश्यक है।
- **वविधि आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन सहायक तकनीकों** के लिये स्टार्टअप के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। डेटा-समर्थित शासन सुनिश्चित करता है कि संसाधन **लक्षति, समावेशी और मापनीय** हों।
- **सामुदायिक सशक्तीकरण और वकिंद्रीकरण:** सामुदायिक सशक्तीकरण और वकिंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है कि दवियांगजनों के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और महासंघों को संस्थागत रूप दिया जाए। साथ ही, उन्हें स्थानीय शासन और विकास योजनाओं में प्रभावी भागीदारी एवं नरिणय लेने को समर्थन दिया जाना चाहिये।
- सामुदायिक शक्तियों पर आधारित **सूक्ष्म वतित, उद्यमिता अनुदान और वकिंद्रीकृत आजीविका मॉडल** को बढ़ावा देना चाहिये।
- नरिणय लेने वाले मंचों में दवियांगजनों का प्रतनिधितिव सुनिश्चित करने के लिये **पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय नकियों को सुदृढ़** बनाया जाना चाहिये। सशक्त समुदाय न केवल **नरिभरता** को कम करते हैं, बल्कि **अनुकूल समावेशन पर आधारित स्थानीय पारसिथितिकी तत्र** का निर्माण भी करते हैं।

नषिकरष:

भारत ने दवियांगजनों के समावेशन की दशिम में उल्लेखनीय प्रगति की है, कति अवसंरचना, शक्ति, रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण में अब भी अनेक बाधाएँ वदियमान हैं। दवियांगजनों का वास्तविक सशक्त भवषिय सशक्तीकरण के 4 ‘E’ — **Equity** (समता), **Enablement** (सक्षमता), **Engagement** (सहभागिता) और **Employment** (रोजगार) पर आधारित है। जब इन सदिधांतों को नीत और व्यवहार, दोनों में समाहित किया जाएगा, तभी भारत कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित समावेशन की ओर अग्रसर हो सकेगा। इस प्रकार का परविरतन यह सुनिश्चित करेगा कि दवियांगजन न केवल सहायता प्राप्त करें, बल्कि राष्ट्र की विकास यात्रा में सक्रिय और समान भागीदारी भी नभिएँ।

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

प्रश्न. “प्रगतशील कानून के बावजूद, भारत में दवियांगजनों को अधिकारों और अवसरों तक अभगिम्यता प्राप्त करने में प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है”। समालोचनात्मक वशिलेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न 1. भारत में लाखों दवियांगजन नविस करते हैं। कानून के तहत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक नशुलक शक्ति।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लिये भूमिका अधमिन्य आवंटन।

3. सार्वजनिक भवनों में रैम्प ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/towards-a-dignified-future-for-divyangjan>

